UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

MAY, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 308

NEWSMAKERS

उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए चीनी क्षेत्र में बड़ी वृद्धि का लक्ष्य रखा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को प्राप्त करने में चीनी उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।राज्य सरकार ने अगले तीन वर्षों के भीतर इस क्षेत्र के सकल मूल्य उत्पादन (जीवीओ) को मौजूदा 1.32 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है।

चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के अनुसार, हाल के वर्षों में जीवीओ ने लगातार वृद्धि दिखाई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,24,198 करोड़ रुपये से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,32,024 करोड़ रुपये तक। विभाग का लक्ष्य मौजूदा स्तरों की तुलना में 2027-28 तक गन्ना उत्पादन में 7% और गुड़ उत्पादन में 10% की वृद्धि करना है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। प्रमुख पहलों में चीनी रिकवरी दर को 9.56% से बढ़ाकर 10.50% करना, 91.54 लाख क्विंटल की समय पर बिक्री सुनिश्चित करना और भंडारण क्षमता का विस्तार करना शामिल है। हाल के वर्षों में, योगी सरकार ने 65 लाख पंजीकृत किसानों तक पहुँच बनाकर गन्ना किसानों के जीवन में काफी सुधार किया है, जिनमें से 46.5 लाख को सीधे सरकारी लाभ मिला है। हाल ही में गन्ने के बकाये के रूप में कुल 2.80 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिससे किसानों की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

Source: Chinimandi, 21st April, 2025

उत्तर प्रदेश: सुपीरियर ग्रुप की चीनी मिल, एथेनॉल और डिस्टलरी प्लांट स्थापित करने की योजना

गोरखपुर : सुपीरियर ग्रुप द्वारा लिंक एक्सप्रेस के दोनों तरफ विकसित हो रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में चीनी मिल, एथेनॉल और डिस्टलरी प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई गई है।सुपीरियर ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने चीनी मिल, एथेनॉल और डिस्टलरी प्लांट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान चर्चा की। हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार, चर्चा में सरैया डिस्टलरी को दोबारा चालू करने की संभावना पर बात नहीं बनने पर नए डिस्टलरी प्लांट को लेकर सैद्धांतिक सहमति बनी। ग्रुप को चीनी मिल के साथ एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए 20 एकड़ जमीन की जरूरत है। प्रबंधन धुरियापार में 1000 करोड़ रुपये के निवेश से एथेनॉल प्लांट लगाने को तैयार दिख रहा है।

ग्रुप द्वारा पिछले वर्ष हुए गीडा दिवस के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सैरया डिस्टिलरी को दोबारा चालू करने को लेकर चर्चा की गई थी। प्रबंधन 150 करोड़ रुपये बैंकों का बकाया और इतना ही कर्मचारियों का बकाया देकर मिल को दोबारा चालू करने को लेकर कवायद कर रहा था। लेकिन 300 करोड़ खर्च के बाद भी सरैया मिल प्रबंधन से बात नहीं बनने पर ग्रुप नये निवेश को लेकर कोशिश में जुट गया है। इसी को लेकर शनिवार को चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। सुपीरियर ग्रुप के उपाध्यक्ष डॉ.सुनील मिश्रा के अनुसार, गोरखपुर में एथेनॉल प्लांट के साथ ही चीनी मिल भी स्थापित करने की योजना है। 1000 करोड़ रुपये के निवेश से प्रस्तावित यूनिट में 300 से 500 लोगों प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। गी डा प्रशासन से 20 एकड़ जमीन की मांग की जा रही है।

Source: Chinimandi, 21st April, 2025

उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वेक्षण के लिये होगा जीपीएस का इस्तेमाल: गन्ना आयुक्त

लखनऊ : पेराई सीजन के दौरान गन्ना और चीनी उत्पादन का सही आकलन लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। इस कड़ी में अब जीपीएस का इस्तेमाल भी शामिल है। प्रदेश में गन्ना उत्पादन के सही आंकलन के लिये जीपीएस के जरिए एक मई से सर्वेक्षण कार्य शुरू होगा। गन्ना सूचना प्रणाली एवं स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हैंड हेल्ड कम्प्यूटर के जरिए यह काम होगा। अगर गन्ना उत्पादन का सही आकलन हुआ तो फिर चीनी उत्पादन का आकलन भी सटीक हो सकता है।

हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार, प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को बताया कि, पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी गई है। सर्वेक्षण कार्य 1 मई से 30 जून तक होगा। गन्ना किसानों द्वारा बोये गये गन्ना क्षेत्रफल के संबंध में विभाग की वेबसाइट enquiry.caneup.in पर घोषणा-पत्र उपलब्ध होंगे। संबंधित किसानों को अपना घोषणा-पत्र स्वयं ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन घोषणा-पत्र उपलब्ध न कराने पर गन्ना किसानों का सट्टा आगामी पेराई सत्र 2025-26 में विभाग द्वारा कभी भी बंद किया जा सकता है। उन्होंने बताया गन्ना सर्वेक्षण कार्य में संबंधित सर्किल के किसान की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सर्वे नीति में पारदर्शिता के दृष्टिगत सर्वे टीम के खेत पर पहुंचने की तिथि, सर्वे टीम के इंचार्ज के नाम व मोबाइल नम्बर की सूचना संबंधित टीम द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से 03 दिन पूर्व किसानों को प्रेषित कर दी जायेगी। गन्ना सर्वेक्षण कार्य संयुक्त टीम के जरिए पूरा होगा।

Source: Sugar Times, 28th April, 2025

P.T.O ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION
वार्ता
The Dialogue
MAY, 2025 Monthly Newsletter of UPSMA VOL: III, ISSUE: 308

केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP 15 रुपये बढ़ाया, नए सीजन के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल होगा दाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2025-26 पेराई सीजन के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) में 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी है

केंद्र सरकार ने गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इस प्रकार अब गन्ने का एफआरपी 355 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2025-26 पेराई सीजन के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) में 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस निर्णय के साथ, गन्ने का FRP अब 340 रुपये से बढ़कर 355 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। नया दाम 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली गन्ना खरीद पर लागू होगा।

केंद्र सरकार ने गन्ने का 355 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी 10.25% चीनी रिकवरी दर के आधार पर तय किया है। इससे अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 3.46 रुपये/क्विंटल का प्रीमियम दिया जाएगा जबकि रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए एफआरपी में 3.46 रुपये/क्विंटल की कटौती होगी। जिन चीनी मिलों की रिकवरी 9.5% से कम है, वहां और अधिक कटौती नहीं होगी और किसानों को गन्ने का एफआरपी 329.05 रुपये/क्विंटल मिलेगा।

देश भर के गन्ना किसान लंबे समय से बढ़ती लागत के कारण गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। हालांकि, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे कई राज्य अपने स्तर पर राज्य परामर्श मूल्य (SAP) तय करते हैं जो FRP से अधिक होता है। यूपी में इस साल गन्ने के एसएपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा एफआरपी बढ़ाने से यूपी जैसे राज्यों पर भी गन्ने के एसएपी में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ेगा। किसानों की ओर से गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की जा रही है। फिलहाल यूपी में अगैती प्रजाति के गन्ने का एसएपी 370 रुपये प्रति क्विंटल है।

चीनी सीजन 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने की उत्पादन लागत (A2+FL) 173 रुपये प्रति क्विंटल मानी है। इस आधार पर सरकार का दावा है कि 355 रुपये प्रति क्विंटल का एफआरपी उत्पादन लागत से 105.2% यानी दोगुने से अधिक है। चीनी सीजन 2025-26 के लिए एफआरपी मौजूदा चीनी सीजन 2024-25 के मुकाबले 4.41% अधिक है।

इससे पहले, फरवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 2024-25 सीजन के लिए गन्ने के एफआरपी को 315 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल किया था। देश में लगभग 5 करोड़ करोड़ किसान और उनके परिजन गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। इसके अलावा लगभग 5 लाख लोग शुगर फैक्ट्री और इंडस्ट्री से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे देश के बड़े राज्यों की राजनीति में गन्ना किसान अहमियत रखते हैं।

Source: Rural Voice, 30th April, 2025

केंद्र सरकार ने शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 जारी किया

नई दिल्ली : 1 मई को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 1966 और चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने से चूके गए कार्यों के संबंध में, केंद्र सरकार ने शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 जारी किया। यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होता है।

भारत सरकार ने शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 1966 की गहन समीक्षा की है, जिसके परिणामस्वरूप नया शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 बनाया गया है। यह संशोधित आदेश चीनी उद्योग के लिए नियामक ढांचे को सरल और आधुनिक बनाने का प्रयास करता है, इसे वर्तमान उद्योग प्रवृत्तियों और तकनीकी प्रगति के साथ संरेखित करता है।

शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 का उद्देश्य घरेलू बाजार में स्थिरता को बढ़ावा देते हुए एक अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह चीनी पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जबकि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को बढ़ाना है।

शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 की मुख्य विशेषताएँ:

चीनी मिलों के साथ डिजिटल एकीकरण –

नए आदेश में डीएफपीडी पोर्टल और चीनी मिलों के ईआरपी या एसएपी सिस्टम के बीच एपीआई-आधारित एकीकरण को अनिवार्य किया गया है, जिससे वास्तविक समय में डेटा साझा करना संभव हो सकेगा। इससे अतिरेक और डेटा लीकेज को कम किया जा सकेगा। 450 से अधिक चीनी मिलें पहले से ही एकीकृत हैं, और चीनी बिक्री पर जीएसटीएन डेटा अब बेहतर निगरानी और दक्षता के लिए लिंक किया गया है।

एकीकृत मूल्य विनियमन –

पिछले चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 के प्रावधानों को नए आदेश में समेकित किया गया है, जिससे विनियमन सुव्यवस्थित हो गए हैं और हितधारकों को अधिक स्पष्टता प्रदान की गई है।

नियमन के तहत कच्ची चीनी को शामिल करना –

कच्ची चीनी अब आधिकारिक रूप से विनियमित है और राष्ट्रीय चीनी स्टॉक गणना में शामिल है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और कच्ची चीनी के लिए "खांडसारी" या "ऑर्गेनिक" जैसे भ्रामक लेबल को समाप्त करता है।

खांडसारी इकाइयों का विनियमन –

पहली बार, 500 टन प्रतिदिन (TCD) से अधिक पेराई क्षमता वाली खांडसारी चीनी मिलों को नियामक निगरानी के अंतर्गत लाया गया है। यह किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) का अनिवार्य भुगतान सुनिश्चित करता है और चीनी उत्पादन डेटा की सटीकता को बढ़ाता है। भारत में 373 खांडसारी इकाइयों में से 66 500 TCD सीमा से अधिक हैं।

Continued on the next page ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

MAY, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 308

मानकीकृत परिभाषाएँ –

विभिन्न चीनी प्रकारों-प्लांटेशन व्हाइट शुगर, रिफाइंड शुगर, खांडसारी शुगर, गुड़, बूरा, क्यूब शुगर और आइसिंग शुगर- के लिए परिभाषाएँ अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित परिभाषाओं के अनुरूप हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में एकरूपता सुनिश्चित होती है।

चीनी उद्योग के नियामक ढांचे को नया रूप देने के लिए, सरकार ने पिछले साल शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर का मसौदा जारी किया था। इसके बाद, 'चीनीमंडी' ने पहले देश के चीनी व्यापारियों, चीनी मिलर्स और अन्य हितधारकों के साथ एक गोलमेज सत्र आयोजित किया था। 'चीनीमंडी' की इस पहल को चीनी मिलर्स और व्यापारी दोनों समुदायों ने खूब सराहा। 15 सितंबर को, भारत भर के चीनी व्यापारी गोवा के डबल ट्री बाय हिल्टन होटल में 'चीनीमंडी' द्वारा आयोजित एक गोलमेज सत्र के लिए एकत्र हुए। सत्र में प्रस्तावित शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर पर गहन चर्चा और मंथन पर ध्यान केंद्रित किया गया। 'चीनीमंडी' ने 6 सितंबर, 2024 को कोल्हापुर में चीनी मिलर्स के लिए एक गोलमेज सत्र भी आयोजित किया था। प्रस्तावित शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर और उद्योग को कैसे स्वस्थ बनाया जाए, इस बारे में मिल मालिकों और व्यापारियों की चिंताओं और सुझावों को 'चीनीमंडी' द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

Source: Chinimandi, 2nd May, 2025

UP TARGETS GROWTH IN SUGAR SECTOR TO BOOST ECONOMY

Lucknow: The sugar industry is poised to play a pivotal role in achieving Chief Minister Yogi Adityanath's ambitious vision of transforming Uttar Pra-desh into a one-trillion-dol-lor economy, with the state govt setting a target to raise the sector's Gross Value Output (GVO) from the cur-rent Rs 1.32 lakh crore to over Rs 1.62 lakh crore within the next three years.

According to the sugar industry and sugarcane development department, the GVO has shown consistent growth in recent years from Rs 1,24,198 crore in the financial year 2023-24 to Rs 1,32,024 crore in FY 2024-25. The department aims to increase sugarcane production by 7% and jaggery production by 10% by 2027-28, compared to current levels.

A comprehensive action plan has been prepared for the current financial year to achieve these targets. Key initiatives include increasing the sugar recovery rate from 9.56% to 10.50%, ensuring the timely sale of 91.54 lakh quintals, and expanding storage capacity.

In recent years, the Yogi govt has significantly improved the lives of sugarcane farmers, reaching out to 65 lakh registered farmers, of whom 46.5 lakh have directly received govt benefits. A total of Rs 2.80 lakh crore has recently been disbursed as sugarcane dues, which is expected to substantially improve the financial well-being of farmers.

Source: TOI, 21st April, 2025

SUGAR MILLS DELAYING PAYMENT TO FARMERS WILL FACE STERN ACTION: YOGI

Lucknow: Chief Minister Yogi Adityanath on Monday directed that the command area allocated to sugar mills for cane procurement should be determined based on their record of payments to farmers.

"The state govt is committed to ensuring timely payments to farmer. Strict action would be taken against mills that delay or neglect payments," Yogi said,

The directives were given by Yogi during a review meeting of the sugar industry and cane development department. During the meeting information on sugarcane price payments, productivity, infrastructure, employment and planes was presented by the officials. The CM emphasised the importance of providing farmers with advanced seeds on time for better sugarcane yield. He stated that agricultural science centers, sugar mills and cane committees must work together for this.

"Representatives from the mills, committee officials and agricultural science center officers should visit fields, observe crop and maintain continuous communication with farmers. Additionally the participation of ministers in farmer meeting should be ensured," he said.

The CM also highlighted the need to empower cane committees further.

Highlighting operational improvement, the CM instructed that the current 142 working days be increased to 155. He also called for a comprehensive review of cooperative and federation sugar mills, including their production capacity and workforce qualifications. During the meeting, Yogi also reviewed the updated status of sugarcane price payments by each mill.

It was reported that during the current govt's tenure. payment amounting to Rs. 2,85,994 crore were made. Which is Rs 72,474 crore more than the Rs 2,13,520 crore paid from 1995 to 2017. Of the Rs 34,466.22 crore due for 2024-25, 83.8% or Rs. 28,873.55 crore. was paid by May 2.

Yogi instructed to stream line the payment cycle to ensure prompt and full payment to all farmers. On the issue of the expansion of sugarcane cultivation, it was noted that the area increased from 20.54 lakh hectares in 2016-17 to 29.51 lakh

Continued on the next page ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

MAY, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 308

hectares in 2024-25. During the same period, productivity rose from 72.38 tons/hectare to 84.10 tons/hectare.

The CM expressed that the-re is potential for doubling production and productivity in Uttar Pradesh with well-planned efforts.

The meeting also revealed that 122 sugar mills, 236 Khandsari units, 8,707 Kolhu units, 65 cogen units, and 44 distilleries operate across 45 districts in the state, collectively providing direct employment to 9.81 lakh individuals.

In terms of ethanol production, it was reported that 150.39 crore litres of ethanol were produced from 102 active distilleries in the state in 2023-24. Additionally, with private investment, an additional production capacity of 105.65 crore litres is being established at a cost of Rs 6,771.87 crore.

Source: TOI, 6th May, 2025

CANE FARMERS TOLD TO DIVERSIFY FOR BETTER YIELD

Lucknow: Principal Secretary, sugarcane development, Veena Kumari, on Wednesday stressed that increasing the productivity of sugarcane is a critical aspect of enhancing the overall output of the sugar industry.

Addressing a conference on 'Business Models on Mitigating Challenges Before the Sugar Industry,' Kumari emphasised that the cultivation of high-yielding varieties of sugarcane and better farm management practices, including optimised irrigation, soil health, and pest control, can help improve the yield per hectare.

She said it was not just about improving sugarcane productivity but also ensuring that farmers can make the most of the land they cultivate. This, she said, included supporting farmers with knowledge about sustainable farming practices, access to quality inputs like fertilisers, and appropriate mechanization for better farm management.

Stressing the need for diversification to produce value-added products, Kumari stated that the sugar industry has been largely dependent on the production of sugar, but diversification is now a necessity to create a more resilient industry. She mentioned that value-added products like ethanol, bio-based chemicals, jaggery, molasses, and other by-products of sugarcane should be developed and promoted.

This not only creates new revenue streams but also makes the industry more sustainable.

Source: TOI, 15th May, 2025

Knowledge Box

A Rare Photo of Sugarcane Research Station, Shahjahanpur: A small power mill driven by a 7-9 HP oil engine was in use at Shahjahanpur. In this photo, variety M 16 is being crushed in 1918. This variety was imported from Mauritius by George Clarke (present in photo). Photo published in 1919.

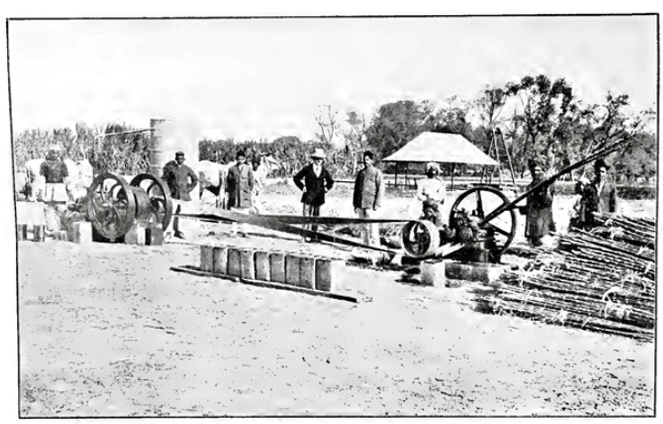

UPSMA Newsletter titled 'Varta' the Dialogue is providing information on sugar, sugar industry and sugar byproducts. We request you to share your thoughts and experience with us through write-ups, success stories, updates, photographs etc. We publish your creative in the next edition of this newsletter. You are requested to send your entries to be published in UPSMA newsletter through mail at upsma@upsma.org. The newsletter will be uploaded on UPSMA website.

अस्वीकरण: यहाँ दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा या अन्य स्रोतों से ली गई है, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है और इस पर इस तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस समाचार में दी गई जानकारी में किसी भी अनजाने त्रुटि से किसी भी व्यक्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए 'वार्ता टीम' किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी इस समाचार की तारीख तक है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य के परिणाम या घटनाएँ इस जानकारी के अनुरूप होंगी।

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org